RNI Regn.No.- 54447/78 स्थापित: 1978 Postal Reg. No. UA/NTL- 08/ 2024-26

पिघलता हिमालय

वर्ष 40 अंक 4 हल्द्वानी सम्वत् 2081 सोमवार 1 जुलाई 2024 एक प्रति 5 रु., वार्षिक-200 रु. आजीवन 2000 रु.

संस्थापक- स्व.आनन्द बल्लभ उप्रेती
स्व.दुर्गा सिंह मर्तोलिया,
स्व.श्रीमती कमला उप्रेती

editorpighaltahimalay@gmail.com
Website-
www.pighaltahimalay.com

सम्पादक : श्रीमती गीता उप्रेती
संरक्षक : फली सिंह दत्ताल
मंगल सिंह मर्तोलिया

उपचुनाव की ताकत से भाजपा-कांग्रेस निकाय के लिये रास्ता बनाएंगे

कार्यालय प्रतिनिधि

-दस जुलाई को मंगलोर और बद्रीनाथ सीटों पर चुनाव
-१३ जुलाई को उपचुनाव का परिणाम सुनाई देगा
-मंगलौर सीट पर भाजपा खाता खोलने को उतावली
-कांग्रेस विपक्षी एकता के साथ ताकत झौंक चुकी

उत्तराखण्ड की दो विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की वोटिंग दस जुलाई को होनी है, इसके लिये भाजपा-कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा बनाते हुए जबर्दस्त माहौल बना दिया है। लोकसभा सीटों पर एकतरफा जीत से गदगद भाजपा मान रही है कि बूथ स्तर तक उसका संगठन मजबूत है ऐसे में वह उपचुनाव भी जीत जायेगी। जबकि कांग्रेस इन सीटों के पूर्व रिकार्ड देखते हुए और विपक्ष के साथ पेंग बढ़ाते हुए मान रही है कि इन दोनों सीटों पर करिश्मा होगा। इस प्रकार मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर ताकत झौंकते हुए दोनों पार्टियां निकाय चुनाव के लिये बनाने लगी हैं। इन्हें मालूम है कि उपचुनाव में जिसका पलड़ा भारी होगा वह निकाय चुनाव में दबदबा रखेगा।

मंगलौर सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन से रिक्त हुई थी। विधानसभा मंगलौर सीट पर राज्य गठन के बाद से अब तक भाजपा का खाता नहीं खुला है। ऐसे में पार्टी ने नई व्यूह रचना की है और प्रत्येक मतदाता से सम्पर्क किया जा रहा है। पिछला रिकार्डों से पता चलता है कि भाजपा का मजबूत प्रत्याशी न होने से कांग्रेस व बसपा इस सीट पर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में लगातार जीत से खुश भाजपा ने 134 बूथों पर तैयारी की है। इसके लिये प्रान्तीय से लेकर मण्डल व बूथ स्तर तक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। मुस्लिम मतदाताओं को साध ने के लिये पूर्व केन्द्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को प्रचार पर उतारा है। जाट मतदाताओं कको रिझाने के लिये सहयोगी दल रालोद के नेता एवं केन्द्रीय मंत्री जयन्त चौधरी को प्रचार अभियान में जोड़ा है। इस सीट पर भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है। कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को अपना उम्मीदवार बनाया है जिससे मुकाबला बहुत ही रोचक हो चुका है।

बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो राजेन्द्र भण्डारी यहाँ कांग्रेस से विधायक रहे लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ली। साथ ही विधायक पद से इस्तीफा दिया। भाजपा ने प्रसाद मिलने की चाह में खुश राजेन्द्र भण्डारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब भाजपा के लिये यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस ने लखपत बुटोला को टिकट दिया है। कांग्रेस सहित विपक्ष इस सीट को हर हाल अपने कब्जे में करना चाहते हैं।

बहुत सीधी सी बात है लोकसभा चुनाव में प्रदेश की पाँचों सीटों को लपकने के बाद भाजपा का उत्साह दुगुना है लेकिन मंगलौर में अभी तक का रिकार्ड देखते हुए और बद्रीनाथ में विधायक का पार्टी बदल कार्य आम मतदाता में कैसी छवी बनाए हुआ है यह सब मतगणना में पता चलेगा। इन परिणामों से यह भी अनुमान लगाना आसान होगा कि चुनाय चुनाव में किस पार्टी का दबदबा बनने वाला है।

निकाय चुनाव के लिये दिग्गज नेताओं की चर्चा होने लगी है

-हल्द्वानी नगर निगम के लिये बेताब हैं करोड़पति
-रुद्रपुर, काशीपुर में नया इतिहास लिखने की तैयारी
-देहरादून, हरिद्वार, रुड़की सीटों पर हाईप्रोफाइल तलाश
-पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर सीटों पर दावे शुरू

उत्तराखण्ड में निकाय चुनाव को लेकर दिग्गजों की चर्चा होने लगी है। चुनाव बुखार में वह नेता ज्यादा तप रहे हैं जिन्हें किन्हीं कारणों से अवसर नहीं मिल सका। अभी सारा मामला सीटों के आरक्षण को लेकर थमा हुआ है लेकिन अपनी दावेदारी करने में कोई पीछे नहीं है।

नगर निगम रुद्रपुर, काशीपुर इस बार नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। कई नेताओ के नाम उछाले जा रहे हैं लेकिन उनके पीछे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद भी देखा जा रहा है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की सीटों के लिये हाईप्रोफाइल तलाश है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से टिकट की मांग करने वालों की लाइन लम्बी होती जा रही है। हल्द्वानी नगर निगम सीट के लिये करोड़पति बेताब दिखाई दे रहे हैं। सीट चाहे सामान्य हो या आरक्षित, दोनों ही स्थिति में धनबल की शक्ति दिखाई देगी। इसके लिये माहौल बनाया जा रहा है।

नगर पालिका पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में पुराने चेहरों को ही दांव पर लगाये जाने की बात हो रही है जबकि गंगोलीहाट, कपकोट, द्वाराहाट सीटों पर युवा नेताओं का दबदबा देखने को मिलेगा। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश सीट पर पुराने नेता मचल रहे हैं लेकिन इस बार नये चेहरों को अवसर मिलना तय है। पौड़ी, मसूरी सीट के लिये भी दावेदार कम नहीं हैं। बेरीनाग, चिलियानौला रानीखेत में दल से ज्यादा निर्दलियों की चर्चा होने लगी है।

हिमालय के लिए अलग नीति की जरूरत

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

पहली बार 09 सितम्बर 2010 को हिमालय दिवस मनाने का जो सिलसिला आरम्भ हुआ वह आज देश की राजधानी में ही नहीं बल्कि हिमालयी प्रदेशों के विभिन्न कोनों में यह आयोजन मनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि पिछले 20 वर्षों में हिमालय में अनियोजित परियोजनाओं के कारण हिमालयीवासी और हिमालय की जैवविविधता खतरे के निशान पर आ चुकी हैयह खतरा खुद ही लोगों ने विकास की अन्धी दौड़ के कारण मोल लिया है। अब मान लिया गया कि पुनः लोग हिमालयी संरक्षण की पुश्तैनी परम्परा को हिमालयी दिवस के बहाने बहाल करेंगे। जिसके लिये मीडिया से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व आम लोगों से लेकर राजनीतिक कार्यकर्ता एवं छात्रों से लेकर नौकरी पेशा लोग हिमालय के संरक्षण के लिये हाथ-से-हाथ मिला रहे हैं। भले यह कारवाँ पाँच वर्षों में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया मगर कारवाँ निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। उल्लेखनीय तो यही है कि पूर्व में हिमालय में बढ़ते खतरों को लेकर राज्य सरकार के पास कोई सोचने का समय नहीं था परन्तु वर्तमान में जिस तरह से लोग 'हिमालय बचाओ' के लिये कारवाँ का हिस्सा बन रहे हैं वह सुखद ही कहा जाएगा। हालांकि हिमालय की जैवविविधता का अब तक विदोहन ही हुआ है यही वजह है कि प्राकृतिक आपदाएँ तथा मौसम परिवर्तन के खतरों का बढ़ना भी जगजाहीर ही कहा जाएगा। कारण इसके घटते जंगल और सूखते जल स्रोतों की चिन्ता अब तक किसी नीति का हिस्सा तो नहीं बन पाये परन्तु आज हिमालय दिवस के रूप में सम्भावना जताई जा रही है कि हिमालयी विकास नीति का कोग्र मॉडल सामने आएगा। हिमालय तथा खुद को बचाने की चुनौती न केवल हिमालयवासियों के सामने है बल्कि दक्षिण एशिया व दुनिया के लिये भी ये एक बड़ी चुनौती है। इन विपरीत परिस्थितियों में हिमालय के लोगों को अपने जीवन-यापन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने लिये जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय समुदायों को अधिकार पाने के संघर्ष करने पड़ रहे हैं। जबकि हिमालय सदैव मैदानों, नदियों तथा सम्पन्न मानव समाजों का निर्माणकर्ता और उनका रक्षक रहा है। आज भी वह भारत सहित कई देशों को कुल मीठे पानी की माँग का 40 प्रतिशत तक देता है। वर्तमान विकास की उपभोगवादी अवधारणा ने हिमालय की उद्र भूमिका को एक सिरे से नकार दिया गया है और यह नजरअन्दाज करते हुए कि हिमालय ब्रिव का एक शिशु पर्वत है ऐसी स्थिति में उसकी रचना व पर्यावरण से छेड़-छाड़ करना घातक साबित हुग्र। फलस्वरूप इसके हिमालय पर्वत परिस्थितिकीय संकट, विकास की गति, गलत नीतियों की वजह से असन्तोष और अशान्ति का केन्द्र बन गया है। जन साधारण की चेतना में हिमालय का अर्थ केवल नदी, पर्वत और पेड़ों से ही होता है जबकि वास्तव में हिमालय अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक फैला हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में लोकतंत्र के संघर्ष, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के जनान्दोलन, राष्ट्र राज्यों के आपसी संघर्ष व मन-मुटाव, राजनैतिक अलगाव व दमन जैसे संघर्षों ने विगत चार-पाँच दशकों से इस पूरे क्षेत्र को एक छद्मयुद्ध का मैदान बना दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे राष्ट्र-राज्यों ने इस विशिष्ट भौगोलिक इकाई के लिये कोग्र पृथक विकास की योजना नहीं बनाई। 09 सितम्बर 2010 से आरम्भ हुग्र हिमालय बचाने की मुहिम ने पृथक हिमालय नीति के लिये बाकायदा एक जन घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है जिसके लिये लगातार हिमालयी राज्यों में संवाद कायम किया जा रहा है। जन-घोषणा पत्र में वे तमाम सवाल खड़े किये गए जिस नीति के कारण मौजूदा भोगवादी सभ्यता की बुनियाद पर आधारित जल, जंगल और खनिज सम्पदाओं के शोषण की गति तीव्र हुई है। विकास के नाम पर वनों का व्यापारिक दोहन, खनन और धरती को डुबोने व लोगों को

शेष पृष्ठ 5 पर

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

पिघलता हिमालय

रवि बडोला की हत्या के बाद सवाल उठने ही हैं

मूल निवास, भू-कानून समन्वय समिति के प्रदर्शन के बाद सरकार हरकत में दिखाई दी है। आन्दोलन की उग्रता देख मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक और एसएसपी को दिवंगत रवि बडोला के घर पर वार्ता के लिये भेजा और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार रवि बडोला के साथ न्याय करेगी।

आंखिर यह सब क्या हो रहा है? क्या पृथक उत्तराखण्ड बनने के बाद यहाँ बाहरी गुण्डे-बदमाश हाबी होना चाहते हैं? क्या पहाड़ी होने की आड़ में भी कुछ गुण्डई होने लगी है? क्या वोटों के खेल में नेता जुगाली करते रहते हैं? असल में राज्य बनने से जिस सुख की उम्मीद की जा रही थी वह अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टा दबंगों की चल रही है। लूट-बलात्कार-हत्या कब्जे-घोटाले जैसे कई मामले उत्तराखण्ड में हो चुके हैं। विगत दिवस दून के नेहरू ग्राम के पास डोभाल चौक पर प्रापर्टी डीलर रवि बडोला उर्फ दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि उसके दो साथी सुभाष क्षेत्री और मनोज नेगी गोली लगने से गम्भीर घायल हो गये थे। हत्याकाण्ड पर न्याय की मांग को लेकर परिजनों व क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति ने उत्तराखण्ड में बढ़ते गुण्डे-बदमाशों के आतंक, मूल निवास १९५० और सशक्त भू-कानून को लेकर प्रदेशव्यापी आन्दोलन शुरू करने का निर्णय लिया। प्रदर्शन की शुरूआत हुई तो समिति के संयोजक मोहित डिमरी के साथ अन्य १२ लोगो की गिरफ्तारी हुई। उन्हें रात्रि में साढ़े दस बजे सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से जमानत पर छोड़ा गया। जमानत पर रिहा होने के बाद मोहित डिमरी ने कहा कि हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं। यही हाल रहा तो मूल निवासियों का वजूद ही खत्म हो जाएगा।

बात रवि की करें, वह कारोबारी था। इसकी हत्या के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद राजस्थान के कोटपुतली जिले के थाना बेहरोल सदर से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी सहित इस गोलीकाण्ड में पाँच पुलिस की पकड़ में हैं। पुलिस के अनुसार देवेन्द्र उर्फ सोनू भारद्वाज और मोनू भारद्वाज निवासी गढ़वाली कालोनी रायपुर देहरादून ब्याज का काम करते हैं, जिसके घर में कुछ दिनों से रामवीर निवासी मुजफ्फरनगर, योगेश निवासी मेरठ और मनीष निवासी पटना बिहार रह रहे थे। रामवीर के खिलाफ हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं और वर्तमान में जेल से पैरोल पर आया हुआ था। पूछताछ में इन लोगों ने पुलिस को बताया कि १५ जून को सागर यादव निवासी नेहरू ग्राम ने रवि बडोला उर्फ दीपक की कार को बिना उसकी रजामंदी के सोनू भारद्वाज के यहाँ सवा चार लाख रुपये में गिरवी रखी थी। जब रवि को इसकी जानकारी लगी तो उसने सागर यादव से अपनी गाड़ी वापस मांगी। यही झगड़ा बढ़ गया और रवि की मौके पर मौत हो गई।

हत्याकाण्ड पर पुलिस कार्रवाई तो होगी लेकिन सवाल है गुण्डों की शरणस्थली उत्तराखण्ड बनकर इसे अशान्त करती रहेगी? सजग रहना होगा।

देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत आगे

ओटावा। नागरिक विमानन के इतिहास में सबसे जघन्य आतंकवाद से सम्बन्धित हवाई दुर्घटना कनिष्क बन बिस्फोट को याद करते हुए बैंकूवर स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारत आतंकवाद की समस्रा से निपटने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने में काम कर रहा है।

थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता

बैंकाक। थाईलैंड की नेशनल असेंबली के उच्च सदन सीनेट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले एक विधेयक को भारी बहुमत के साथ मंजूरी दे दी। इसके साथ ही थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है।

ताजिकिस्तान में हिजाब पर पाबंदी

दुशांबे। ताजिकस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक लग गई है। 96 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले देश की सांसद में यह फैसला लिया गया। नए संशोधनों के अनुसार कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रस्ताव प्रशासनिक उल्लंघन सहिता में संशोधन को मंजूरी के बाद पास हुआ

हिन्दूजा परिवार के चार सदस्यों को सजा

जिनेवा। स्विट्जरलैंड की एक आपराधिक अदालत ने अमीर हिन्दूजा परिवार के चार सदस्यों को उनके कमजोर घरेलू कामगारों का शोषण करने के लिए चार से साढ़े चार साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने मानव तस्करी के गम्भीर आरोपों को खारिज कर दिया।

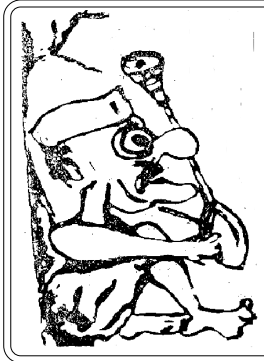

फसक

दाज्यू, चाहे किसी भाव मिले प्रसाद जरूरी ठैरा

जब कोतवाल अपना हो तो शर्म-बेशर्म बराबर होता है बल

दाज्यू, भवाली-अल्मोड़ा हाईवे के बीच कैंची धाम मेले में मालपुआ खाने के बाद मलीम सिंह और पन्नू अभी तक आराम कर रहे हैं। कह रहे थे- 'बाबा की शक्ति और भक्ति देखने के बाद अब कुछ करने का मन नहीं है।' दाज्यू, मन तो हमारा भी बहुत कर रहा था एक बार कैंची मेले जाएं लेकिन भीड़ देखकर सांस फूलने लगा। जबकि भण्डारे का अपना ही मजा होने वाला ठैरा। हमारे शहर में रिक्शा यूनियन वालों ने भी भण्डारे में हलुवा बंटवा दिया। रातभर तारादेव और ज्योति गणेश चिल्लाते हुए गा रहे थे। पाण्डाल में सात-आठ लोग लेते थे। सुबह होते ही भण्डारे में भीड़ जुट गई। माहौल बनते ही भीड़भाड़ का पगल्योट होता है बल।

कैंची धाम ही देख लो, राह चलते सुनसान इस सुन्दर से स्थान पर गिनती भर के लोग आया-जाया करते थे लेकिन अब भयंकर भीड़ होने लगी है। भीड़ के ऊपर भीड़ चलने को तैयार है। आस्था के सैलाब को भला कौन रोक सका है? आस्था के इस लम्बे सफर में दुकानदारी भी हो जाने वाली ठैरी। लाला झम्मन लाल ने लाल झण्डे, दुपट्टे, गम्छे और जयराम ने मिठाई प्रसाद की दुकान खोल ली है। चरन सिंह वाहन पार्किंग का ठेका अपने नाम करवा चुका है। दाज्यू, ये सब भी बहुत जरूरी है। जब भीड़ होगी तो प्रसाद बंटने से ज्यादा बिकेगा। ब्रेकफास्ट, लन्च, डीनर के लिये रेस्टोरेंट और रहने के लिये होटल भी खुलेंगे।

परगट सिंह ने भी अपने गाँव में गुफा की खोज करते हुए माहौल बनाया था लेकिन दो-चार अखबारों में सुर्खियों के बाद सब शान्त हो गये। सोच रहे हैं अब किसी मुख्यअतिथि को बुलाकर सत्कार किया जाए। ठेकेदार जमन दा भी एकदम तैयार है। कह रहे थे- 'गाँव में कुछ काम नहीं है, भक्तों का आना-जाना हो जाए तो मन लगा रहेगा। बच्चे मोबाइल खेल में लगे हुए हैं।' दाज्यू, फोड़ाफोड़ मच रही है। बस में सीट को लेकर नैनीताल बस अड्डे पर भिड़ रहे यात्रियों को पुलिस ने लठियाया बल। यात्री हैं बेसुमार, कहाँ से आएं बस....। दाज्यू, हम तो कह रहे हैं चाहे किसी भाव आए प्रसाद जरूरी ठैरा।

दाज्यू, खुशी की बात है कि हमारे भगतदा स्वस्थ्य हो गये हैं। जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिये डिफेंस कालोनी देहरादून स्थित उनके आवास पर कई लोग पहुँचे। हरदा भी एकदम ठीक हैं। उनका कहना है- 'पलायन से पहाड़ खाली हो रहे हैं और बाहर से आकर लोगों ने घेरबाड़ करनी शुरू कर दी है।' दाज्यू, सब अपनी करनी कर रहे हैं किसको क्या कहें? सीएम पुष्कर धामी ने तो सीधे कहा है कि जमीन खरीदने वालों का रिकॉर्ड और उद्देश्य पता लगाएं। दाज्यू, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि गुण्डई-लफड़ा कर बहुत सारे उत्तराखण्ड में भाग आए हैं और गड्ढे में घुस रहे हैं ताकि उनकी जड़ जम सके। कुछ दिन रहने के बाद सरासार होने वाली ठैरी।

अवतार सिंह बता रहा है- 'पटरी पार वाले डिग्री कालेज में बुलरुवा गायब हो गया था। कुछ दिनों में प्रकट हुआ और मछली-अण्डे-पकौड़ी की बात करते हुए बहलाने लगा। तभी साहब ने अपनी आंखें बन्द कर ली हैं, चाहे जो करो।' दाज्यू, बीमारी का दावा करने वाले बिना फिटनेस के कालेज में घुस रहे हैं बल। ऐसा ही मामला इधर भी हुआ तब एहड़कम्प मच गया और साहब ने तुरन्त फिटनेस का प्रमाण पत्र लाने को लिख दिया। लेकिन आप जानने ही वाले ठैरे कि जब कोतवाल अपना हो तो शर्म-बेशर्म बराबर होता है बल। ऐसे में छेड़छाड़, लूटपाट, लपटझपट तो सहज बात हुई। भगवान बचाए, इन सबसे। दाज्यू, देहरादून में कुछ सचिवों ने तो अपने दफ्तरों के बाहर सन्देश चस्पा कर दिये हैं बल कि तबादलों के सम्बन्ध में उनसे कोई मुलाकात न करे। यही होना चाहिये।

-तुम्हारा भुली झकरुवा

बिनसर मामले में आइएफएस एसोसिएशन ने सरकार को पुनर्विचार को कहा

शासन की कार्यवाही से आइएफएस अधिकारी नाराज

देहरादून/हल्द्वानी। सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा के अन्तर्गत बिनसर अभ्यारण्य के जंगल में हुई आग की घटना के प्रकरण में तीन आरएफएस के विरूद्ध की गई कार्रवाई से आइएफएस एसोसिएशन ने सरकार को पुनर्विचार को कहा है। चल रही बहस के बीच 5 अधिकारियों ने एसोसिएशन छोड़ दी। उनका कहना है कि इस मामले में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बावजूद इसके एसोसिएशन ने दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। एसोसिएशन ने सीएम को ज्ञापन भेजकर बिनसर मामले में की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार करने को कहा है। बिनसर अभ्यारण्य में 13 जून को लगी आग को बुलझाने के प्रयास में चार कर्मियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि चार घायलों में से इलाज के दौरान एक ने दिल्ली में दम तोड़ दिया। सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य वन संरक्षण को वन मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया, मुख्य वन संरक्षक व डीएफओ के विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाई की गई। इस प्रकार की कार्रवाई से तममा आइएफएस अधिकारियों में रोष है। संगठन में उठी बात में कहा कि यदि एसोसिएशन उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो इसे संगठन में क्यों रहा जाए।

अज्ञात पर केस, अब चलेगी जाँच, होगी पड़ताल!!!

अल्मोड़ा। बिनसर अभ्यारण्य वनाग्नि मामले में छह दिन बाद वन विभाग ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया। कहा कि घटनास्थल के नजदीक रिसाल गाँव स्थित है। आशंका है कि इसी गाँव या इसके आसपास के किसी व्यक्ति ने जंगल में आग लगाई थी। कोतवाली में मामला दर्ज होने के बाद सवाल खुरच-खुरच कर किये जा रहे हैं कि विभाग इतने दिनों में जागा इत्यादि।

अब अज्ञात के खिलाफ वन में आग और गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है तो जाँच होगी ही। वैसे भी जाँच कई बिन्दुओं से हो रही है। इस पूरी जाँच के अलावा पड़ताल करने वाले सक्रिय हैं और कहना है कि यह सब पहली बार नहीं हो रहा है। जंगल में आग की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वनों को सुरक्षित रखने के लिये अधिकारी, नेता, जनता अकेला कुछ नहीं होता। सबने कोशिश करनी है। जंगल हमारा जीवन हैं।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

जंगली फल

'हिसालु' पहचान के लिये मोहताज

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

हिसालु भारत में लगभग सभी हिमालय राज्य में पाया जाता है। भारत के अलावा यह नेपाल, पाकिस्तान, पोलैंड आदि पहाड़ी देशों में भी पाया जाता है। विश्व भर में हिसालु की लगभग 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं। हिसालु बहुत ही दिव्य औषधि के रूप में भी काम करती है। उत्तराखण्ड की पहाड़ी वादियों में आसानी से देखने को मिल जाएगा आपको हिसालु।

पहाड़ की रूखी-सूखी धरती पर छोटी झाड़ियों में उगने वाला यह फल या बेरी जंगली रसदार फल है जो देखने में आकर्षित तो लगता ही है वहीं अपने औषधीय तत्वों के लिए भी विख्यात है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिसालु जेठ-अषाड़ के महीने यानी की मई-जून के महीने में आसानी से देखने को मिल जाएगा। जंगली झाड़ियां आपको इनके फल से लकदक नजर आएंगी। कुछ स्थानों पर इसको हिंसर या हिंसरु के नाम से भी जाना जाता है। इसका लेटिन नाम Rubus elipticus है, जो कि Rosaceae कुल की झाड़ीनुमा वनस्पति है। हिसालू दो प्रकार के होते हैं जो पीला और और काले रंग का होता है। पीले रंग का हिसालू आम है लेकिन काले रंग का हिसालू इतना आम नहीं है। एक अच्छी तरह से पका हुए हिसालू का स्वाद मीठा और कम खटा होता है। यह फल इतना कोमल होता है कि हाथ में पकड़ते ही टूट जाता है एवम् जीभ में रखो तो पिघलने लगता है। इस फल ने कुमाऊँ के लोकगीतों में एक खास जगह बनाई है, पहाड़ो में इस फल के आगमन के समय पर्यावरण में खुशी की झलक दिखाई देती है। इस फल को ज्यादा समय तक सम्भाल के नहीं रखा जा सकता है क्योंकि हिसालू फल को तोड़ने के 1-2 घण्टे बाद ही खराब हो जाता है।

इस फल के बारे में प्रसिद्ध कवि गुमानी पन्त भी लिखते हैं-

हिसालू की जात बड़ी रिसालू,
जाँ जाँ जाँछे उधेड़ि खाँछे।
यो बात को क्वे गटो नी माननो,
दुद्याल की लात सौणी पड़छ।

यानी हिसालू की नस्ल बड़ी नाराजगी भरा है, जहाँ-जहाँ जाता है, बुरी तरह खरोंच देता है, तो भी कोई इस बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि दूध देने वाली गाय की लातें खानी ही पड़ती हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हिसालू फलों में प्रचुर मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा होने की वजह से यह फल शरीर के लिए काफी गुणकारी माना जाता है। हिसालू में पोषक तत्वों की कोई कमी नही है इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, सोडियम व एसकरविक एसिड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसमें विटामिन सी 32 प्रतिशत, फाइबर 26 प्रतिशत, मैंगनीज़ 32 प्रतिशत व मुख्य रूप से में लौ गलीसमिक, जिसमें शुगर की मात्रा सिर्फ 4 प्रतिशत तक ही पायी गयी है। इसकी जड़ को बिच्छुघास की जड़ एवं जरुल की छाल के साथ कूटकर काढ़ा बनाकर बुखार के रोगी के लिए रामबाण दवा है। इसकी पत्तियों की ताजी कोपलों को ब्राह्मी की पत्तियां एवं दूर्वा के साथ मिलाकर स्वरस निकालकर पेप्टिक अल्सर की चिकित्सा की जाती है। इसके फलों से प्राप्त रस का प्रयोग बुखार,पेट दर्द, खांसी एवं गले के दर्द में बड़ा ही फायदेमंद होता है। छाल का प्रयोग तिब्बती चिकित्सा पद्धति में भी सुगन्धित एवं कामोत्तेजक प्रभाव के लिए किया जाता है। हिसालू फल के नियमित उपयोग से किडनी-टानिक के रूप में भी किया जाता है। यही नहीं इसका प्रयोग मूत्र आना (पोली-यूरिया), योनि-स्राव, शुक्र-क्षय एवं शय्या-मूत्र (बच्चों द्वारा बिस्तर गीला करना) आदि की चिकित्सा में भी किया जाता है।

हिसालू जैसी वनस्पति को सर्रक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए इसे आई.यू.सी.एन. द्वारा वल्ड्र्स हंड्रेड वर्स्ट इनवेसिव स्पेसीज की लिस्ट में शामिल किया गया है एवम् इसके फलों से प्राप्त एक्सट्रेक्ट में एंटी-डायबेटिक प्रभाव भी देखे गए हैं। इस फल का कोई मालिक नहीं है। न ही आम आदमी न सरकार। हालाँकि हिसाव जैसी वनस्पति को सर्रक्षित किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए इसे आई.यू.सी.एन द्वारा वल्ड्र्स हंड्रेड वर्स्ट इनवेसिव स्पेसीज की लिस्ट में शामिल किया गया है।

सूचीबद्ध होने से भी क्या हुआ? हिसालु को सूची में शामिल कर दिया गया परन्तु ग्राउण्ड लेवल में कोई गतिबिधि नहीं दिखती न कभी दिखी। उत्तराखण्ड 23 साल का युवा राज्य है। इस दौरान सरकारें आयी और गयी लेकिन सरकारों ने हिसाव खाये लेकिन किया कुछ नहीं। फल की तारीफ की बन्द कमरों में, चर्चा की, हुआ कुछ नहीं। इसको ग्राम पंचायत से जोड़ने की जरुरत है ताकि इसका उत्पादन किया जा सके और गाँव में ही लोगों को इसका फायदा हो जिनके मा यम से यह दवाई के रूप में और फल के रूप में जितना भी पहुँचे लेकिन पहुँचे बाहरी बाजारों में। उत्तराखण्ड के बाहर के लोगों को न के बराबर इसके बारे में पता है क्योंकि उन तक पहुँच नहीं पाता दूसरा सरकार की तरफ से कोई प्रचार प्रसार कोई योजना नहीं है। जब लगाया जाएगा तो कितना उत्पादन हो जाएगा। उत्तराखण्ड में हिसालू का उत्पादन कहीं पर नहीं होता है। इसके बावजूद गर्मियों में नैनीताल जैसे हिल स्टेशन की सड़कों पर 30 रुपया प्रति सौ ग्राम की दर से हिसालू बिकता दिखता है। सैलानी जिसे 300 रुपया किलो खरीद रहे हैं। दो महीने के लिए 'हिसाव खाने आओ कैम्पेन' चलाने की जरुरत है। उससे पहले इसको जंगल से घर लाने की जरुरत है। इसका प्लान्ट लगाने, बाग़ लगाने की जरुरत है ताकि आगे उत्पादन किया जा सके। पर्यटक भी आयेगा और आम जन के साथ राज्य सरकार को भी फायदा होगा। राज्य को रेवन्यू मिलेगा, आँखिर बूंद-बूंद से सागर भरता है। लेकिन करे तो कोई। हिसालू ऐसा फल है जिसे लगाने की जरुरत नहीं है अपने आप उगता है। औद्योगिक रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है जैसे जैम, जैली, विनेगर, चटनी व वाइन आदि में। साइट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड का काफी अच्छा स्रोत इसे माना गया है। उत्तराखण्ड के जंगल में मिलने वाले फलों को बाजार से जोड़कर आर्थिकी संवारने का जरिया बनाया जा सकता है। जो फल हम फ्री में खाते हैं या जंगलों में ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, वास्तव में उनकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाओगे। सरकार अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं कर पायी है।

ज्योतिष की बातें - 184

7 जुलाई 2024 को शुक्र शत्रुराशि कर्क में प्रवेश करेगा। इसके पूर्व 5 जुलाई को पश्चिम में शुक्र उदय भी हो जाएगा। अत: कुल मिलाकर शुक्र निर्बल ही रहेगा। शुक्र भौतिक सुख, सांसारिक लाभ, सफलता, धन सम्पत्ति, वाहन, वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रकरण आदि का कारक होता है। फलदीपिका के अनुसार शुक्र छठवें, सातवें और दसवें स्थान पर अशुभ होता है अन्य स्थानों पर शुभ होता है। साथ ही मकर और कुम्भ राशियों के लिए योगकारक भी होता है। अत: अगले 24 दिन शुक्र अपने कारक विषयों में सभी राशियों को सामान्य फल ही प्रदान करेगा।

रथ यात्र- आषाढ़ शुक्ल द्वितीया उदयव्यापिनी न्यूनतम त्रिमुहूर्ता तिथि में भगवान जगन्नाथ की रथयात्र का उत्सव मनाया जाता है। पुष्य नक्षत्र होने पर विशेष फलदायी होता है। इस बार तदनुसार रविवार 7 जुलाई 2024 को पुष्य नक्षत्र के संयोग में रथयात्रा का पर्व मनाया जाएगा।

शुभं भवतु !!

-ओंकार नाथ कोष्टा
ज्योतिर्विद् एवं आयुर्विद्

सम्यक् विचार- 75

निरन्तर परिवर्तन आवश्यक

सोचिए जरा! एक कॉलेज में हमेशा के लिए एक प्रधानाचार्य बना दिया जाए, शिक्षकों में भी कोई परिवर्तन न हो, वहाँ के किसी भी स्टाफ में परिवर्तन न हो, किसी का कभी कोई प्रमोशन भी न हो, सभी एक ही कुर्सी पर बैठे रहें तो कैसा लगेगा? जिले में वही स्थायी डीएम, उसका पूरा स्टाफ भी वही बना रहे, किसी का कभी कोई प्रमोशन न हो, तो जिले का क्या होगा? बैंक में भी वही मैनेजर हमेशा के लिए बना रहे, आरटीओ भी 20-25 साल तक एक ही व्यक्ति बना रहे तो क्या होगा? आपके गाँव का प्रधान भी हमेशा के लिए किसी एक व्यक्ति को बना दिया जाए, विधायक भी क्षेत्र का एक ही सदैव के लिये निश्चित कर दिया जाए तो कैसा रहेगा?

यदि कोई परिवर्तन न हो तो धीरे-धीरे नीरसता आ जाती है, फिर निष्क्रियता भी रहती है और धीरे-धीरे विकास भी स्थगित हो जाता है। 20-25 वर्ष तक एक ही मंत्री, मुख्यमंत्री बना रहे तो उस राज्य का विकास थम जाता है।

मेरे विचार से किसी भी स्थान पर, किसी भी कार्यालय में, किसी भी पद पर निरन्तर परिवर्तन होना आवश्यक है। छोटे पदों पर कार्यकाल अधिक हो सकता है लेकिन उच्च पदों कार्यकाल भी अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी पद पर एक व्यक्ति को दो कार्यकाल से अधिक अवसर नहीं मिलना चाहिए। अमेरिका में भी कोई व्यक्ति दो बार से अधिक अर्थात 8 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। ऐसा नियम यहाँ भी बनना चाहिए।

-सरल

कैबिनेट बैठक में १२ प्रस्तावों पर मुहर

देहरादून। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखण्ड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें बैंक के साथ एमओयू करने की मंजूरी देकर उन्हें सैलरी एकाउंट पर मिलने वाले पैकेज की राह खोली है। सहकारी समितियों की प्रबन्ध समितियों में अध्यक्ष व सदस्यों के 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं।

महिलाओं को सहकारी प्रबन्धन समिति में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य हो गया है। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए कैबिनेट ने एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है। इसके लिये मॉत्रिमण्डल ने विधेयक को मंजूरी दी है। पहले चरण में देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार के तहत परिवहन विकास, संचालन, रखरखाव, निगरानी व पर्यवेक्षण का कार्य होंगे।

कैबिनेट के फैसलों में बिजली सुरक्षा तन्त्र को मजबूत करने के लिए विभागीय ढांचे में 89 नए पदों को मंजूरी दी गई। चिकित्सक, सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है इससे चिकित्सा विशेषज्ञ अब 65 साल में रिटायर्ड होंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में खाद्य पदार्थों के पीरक्षण के लिए मोबाइल इकाइयां फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन आठ आउटसोर्स को मंजूरी मिली है। महासू देवता मास्टर प्लान के लिए विस्थापन नीति पर मुहर लग चुकी है। पर्यटन नीति 2018 में संशोधन हुआ है।

वनाग्नि और सड़क हादसों में हो रही मौतों के लिए तत्काल जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरुरत

हल्द्वानी। वनाग्नि और सड़क हादसों में हो रही मौतों के लिए तत्काल जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरुरत पर बल देते हुए उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच ने कहा है कि जनसहभागिता के बिना वनाग्नि पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता है।

शहीदों के सपने को साकार करने के मूल उद्देश्य से विचार मंच के रूप में गठित इस मंच के संस्थापक संयोजक रमेश चन्द्र पाण्डे ने बिनसर में बनाग्नि में जिन्दा जले चार कार्मिको की मौत पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि फायर सीजन के पीक पीरियड में जब उत्तराखण्ड के जंगल आग से धधक रहे थे उस समय वनाग्नि के नियन्त्रण को लेकर गम्भीर होने के बजाय हर स्तर पर जमकर राजनीति हो रही थी जिसके चलते सोमेश्वर तहसील में दो अलग अलग हादसों में 5 लोग बनाग्नि की भेंट चढ़ गये। विकास के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर मुखर पाण्डे ने कहा फायर सीजन के इस पीक पीरियड में हाइकोर्ट शिफ्टिंग के मामले में जमकर राजनीति हुई और कोर्ट के आदेश पर इस मामले में जनमत संग्रह भी कराया गया लेकिन बनाग्नि नियन्त्रण के उपाय हेतु सुझाव लेने के लिए जनमत संग्रह कराने की जरुरत किसी ने नहीं समझी जबकि वनाग्नि नियन्त्रण हेतु जन सहभागिता बेहद जरुरी है। कहा कि बनाग्नि की निगरानी और चौकसी हेतु इतने क्रू सेन्टर के साथ ही लावलस्कर होने के बाद भी लम्बे समय से जंगलों में आग लगने के स्पष्ट कारणों के उजागर नहीं होने से कई सवाल उठ रहे हैं। आये दिन सड़क हादसों से हो रही मौतों से हर कोई सहमा है । उन्होंने ऐसे हादसों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने की जरूरत पर बल दिया है।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

बारिश के लिये जल कुंड भरा

गंगोलीहाट। सूखे से परेशान क्षेत्र के लोगों ने बारिश के लिये प्राचीन पाण्डव मन्दिर स्थित जलकुण्ड को भरा। मान्यता है कि जब भी सूखे के हालात हों चहज स्थित पाण्डव मन्दिर में सामूहिक रूप से बारिश की कामना करते हुए ऐसा किया जाता है। इससे इन्द्रदेवता प्रसन्न होते हैं। चहत के तल्ला नौले में स्नान के बाद तीन किमी खड़ी चढ़ाई चढ़कर लोगों ने जलकुण्ड को भरा।

गंगोली बाजार में गन्दगी का अम्बार

गंगोलीहाट। नगर पालिका क्षेत्र में गन्दगी के अम्बार से क्षेत्रवासी परेशान हैं। व्यापारियों ने पालिका के प्रति रोष जताते हुए कहा कि महाकाली मन्दिर को जाने वाले पैदल मार्ग की दशा खराब होती जा रही है। जाह्नवी नौले के पास भी बिच्छू घास सहित कूड़ा फैल रहा है। पोस्टआफिस लाइन में भी कूड़े के डेर से व्यापारी नाराज हैं।

छारछुन में पुल बनने से होगा लाभ

धारचूला। मल्ला छारछुन में 32.98 करोड़ की लागत से बने पुल के दोनों देशों को लाभ होगा। इस मोटर पुल से आवाजाही होने से सीमान्त वासियों को सुविधा होगी। भारत-नेपाल के बीच रोटी-बेटी के रिश्ते होने से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। इसके लिये वर्तमान में 11 पुल बने हैं। इनमें झूलाघाट, द्यौड़ा, द्वालीसेरा, जौलजीवी, बलुवाकोट, धारचूला, तिगड़म, बड़ूजुम्म, मलघटया जयकोट, गस्कू माल और सीतापुल शामिल हैं।

टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन काम शुरू होगा

चम्पावत। केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। श्री टम्टा ने इस मौके पर कहा कि अल्मोड़ा के विकास का खाका तैयार किया जा रहा है। प्रदेश की सड़कों को हाटमिक्स किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन की कार्ययोजना तैयार है। शीघ्र इसका काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अल्मोड़ा सड़क को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। यह हाइवे मिशाल पेश करेगा।

केन्द्र सरकार में राज्यमंत्री पद पाने के बाद अजय टम्टा जगह-जगह कार्यक्रमों में जाकर कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं।

अब मिलम तक पहुँच आसान, सड़क कटान-मिलान कार्य पूरा

जोहार। चीन सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मिलम तक अब पहुँच आसान हो चुकी है। यहाँ सड़क कटान-मिलान का कार्य पूरा हो चुका है। मुनस्यारी से मिलम तक 65 किमी मोटर मार्ग चीन सीमा पर चौथी सड़क है। इससे पहले चीन समाल पर सोबला-दारमा, तवाघाट लिपुलेख और गुंजी-ज्योलिंगकांग सड़क बनी। प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले की चीन से सबसे लम्बी सीमा सीमा है। इस सड़क के बनने से सेना, सीमा सड़क संगठन के दल, स्थानीय लोगों को सुविधा होगी।

1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद जोहार क्षेत्र पलायन के चलते काफी बदला लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति लोगों का लगाव ही है जो माइग्रेशन में आना-जाना जारी है और परम्परागत पूजा में एकत्रित होते हैं। जोहार में मिलम, मर्तोली, टोला, बुर्फू, लास्पा, ल्वा, रिलकोट, गनघर, बिल्जू, खिलांच सहित अन्य ग्राम हैं। सड़क की मांग को लेकर क्षेत्रवासी पहले से मांग कर रहे थे। इस बीच शासन द्वारा होमस्टे को प्रोत्साहन के कारण भी राह दिखाई दी है।

बेरीनाग में पानी, थल में बिजली गुल

बेरीनाग। नगर क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। एक-एक सप्ताह में पानी मिलने से नाराज लोगों ने आन्दोलन की चेतावनी दी है। 15 हजार की आबादी वाले शहर व आसपास में नौले-धारों में जाकर जैसे तैसे प्यास बुझाई जा रही है। सूख चुके जलस्रोतों पर रात से ही लाइन लगानी पड़ती है। ऐसे में पशुपालकों को और भी ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। पेयजल संकट पर जेई महेश रौतेला ने बताया कि गोरघटिया पम्पिंग पेयजल योजना में मात्र 1.5 एमएम पानी है। नगर को 3 एमएलडी पानी की आवश्यकता है। बिजल कटौती से भी पेयजल आपूर्ति में बाधा आ रही है। जल संस्थान पिकप वाहन से पानी की आपूर्ति कर रहा है।

उधर थल में बिजली व्यवस्था लड़खड़ाने पर व्यापार मण्डल सहित क्षेत्रवासी बेहद नाराज हैं। व्यापार मण्डल अध्यक्ष गंगा सिंह मेहता के नेतृत्व में व्यापारियों ने अवर अभियन्ता से भेंट की। अवर अभियन्ता नवल निर्खुपा का कहना है कि नगर के डाफिला मोड़ के पास 33 केवी लाइन में चीड़ के पेड़ गिरने से फाल्ट आया था, उसे ठीक कर दिया गया है।

कपकोट : मनमाने बिजली बिल

बागेश्वर। कपकोट में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से मनमाने बिल वसूले जाने का आरोप लग रहा है। शिकायतें सहित क्षेत्रवासियों ने विधायक कार्यालय पहुँचकर अपनी समस्या बताई। कहा कि विभाग उपभोक्ताओं का शोषण कर रहा है।

कपकोट क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा मनमाने बिल वसूलने की शिकायत लम्बे समय से मिल रही है। ग्रामीण अब तक कई बार इन बिलों को जमा कर चुके हैं। गत दिनों मीटर रीडर द्वारा पोथिंग गाँव में रीडिंग की जा रही थी, देखते ही ग्रामीण भड़क गये। बिल देखकर नाराज ग्रामीण विधायक सुरेश गड़िया के कार्यालय में गये और अपनी समस्या रखी। विधायक ने ग्रामीणों की सुनने के बाद अधिशासी अभियन्ता यूपीसीएल को तुरन्त गाँव में मिली शिकायतों का शिविर लगाकर निराकरण करने को कहा। विधायक से मिलने वालों में नैन सिंह, भुवन चन्द्र जोशी, गोविन्द बल्लभ, प्रताप सिंह आदि थे।

मिलम : रास्ता बन्द करने का आरोप

मुनस्यारी। मल्ला जोहार विकास समिति ने मिलम के ढुंग टोपी ढूंगा पैदल मार्ग बन्द किए जाने का सेना पर आरोप लगाते हुए रोष प्रकट किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। समिति के अध्यक्ष श्रीराम सिंह धर्मशक्तू ने बताया कि सीमान्त क्षेत्र के निवासी माइग्रेशन के दौरान 6 माह के लिये उच्च हिमालयी की ओर निवास करने जाते हैं। इस दौरान वे अपने साथ बड़ी संख्या में भेड़, बकरी व अन्य मवेशियों को ले जाते हैं। मिलम गाँव आर्मी कैम्प से टोपी ढूंगा तक पहुँचने वाला पैदल मार्ग आम मार्ग है। कई वर्षों से ग्रामीण माइग्रेशन के दौरान उक्त रास्ते का इस्तेमाल आवाजाही के लिये करते हैं। आरोप लगाया कि कह कुछ समय से सेना ने इस पैदल मार्ग को बन्द कर दिया है। जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है।

राममंदिर में अतिक्रमण की शिकायत

हल्द्वानी। शहर के रामलीला मोहल्ला स्थित प्राचीन राम मन्दिर में अतिक्रमण सम्बन्धी शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया और तय हो चुका है कि सार्वजनिक सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होगा और इसके लिये अभी आगे भी पूछताछ के साथ ही जिला प्रशासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व पार्षद हितेश पाण्डे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर शिकायत की थी कि मन्दिर परिसर बिना अनुमति के आवासीय मकान और दुकान का निर्माण हो रहा है। जाँच में सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार ने पाया एक अर्द्ध निर्मित निर्माण है जो विधायक निधि से स्वीकृत हुआ था लेकिन बजट न मिलने के कारण बन्द हो गया। अधिकारियों ने पुजारी के बारे में भी जानकारी ली। मन्दिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, मंत्री समेत शिकायतकर्ता का पक्ष भी सुना गया। यह पूरी रिपोर्ट प्रशासन के पास जाएगी।

बताते चलें कि रामलीला मोहल्ला, रामलीला मैदान, राम मन्दिर हल्द्वानी के इतिहास में पुरानी धरोहर है। इस सार्वजनिक स्थान पर पिछले कुछ वर्षों से एकाधिकार के लिये नज़र लगी हुई हैं और किसी न किसी बहाने हस्तक्षेप है।

जोशीमठ : सुनवाई १३ अगस्त को

नैनीताल। जोशीमठ में लगातार हो रहे भू-धंसाव को लेकर पी.सी.तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अब अगली सुनवाई 13 अगस्त तय कर दी गई है। हाईकोर्ट मे परियोजना में ब्लास्टिंग और निर्माण के विरोध में उपपा व चिपको आन्दोलन के सदस्य पी.सी. तिवारी ने जनहित याचिका दायर की है।

सचिवालय में भर्तियों पर जवाब

नैनीताल। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय से पूछा है कि पूर्व के आदेश पर क्या कार्यवाही हुई है। अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने पूर्व में हुई सुनवाई में सरकार, विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिये थे कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर शपथपत्र के माध्यम से रिपोर्ट पेश करें लेकिन इसे तय समय से पेश नहीं किया गया है।

परिक्रमा

भीमताल झील से सिल्ट सफाई कार्य

भीमताल। सिंचाई विभाग ने इस बार भीमताल झील से सिल्ट सफाई का बेहतर कार्य किया। झील में सिल्ट अधिक होने से मशीन तक फंस गई, जिसे निकालने के लिये दूसरी मशीन का सहारा लिया गया। विभाग की ओर से झील से सिल्ट निकालने के लिये 30 लाख की धन राशि पर व्यापारियों ने सवाल खड़े किये हैं कि इस राशि से पूरी सफाई नहीं हो पायेगी। बरसात होते ही फिर सिल्ट भर जाएगी।

पन्तनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रक्रिया, विधायक की चेतावनी

पन्तनगर। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पन्तनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि पन्तनगर में अन्तर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस अड्डा होगा। सीएम ने कहा कि यहाँ नाइट लैंडिंग की सुविधा भी होगी। लालकुआ-पन्तनगर मार्ग का भी एलाइमेंट बदला जाएगा। इसके लिये राज्य सरकार की ओर से 164 करोड़ की धनराशि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दी है।

मुख्य सचिव रतूड़ी ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बैठक के दौरान बीज एवं तराई विकास निगम, पन्तनगर विवि, लोनिवि, सिडकुल, कृषि विभाग व तराई स्टेट फार्म को अपनी परिसम्पत्तियों का आंकलन कर तत्काल अपने विभागों के माध्यम से शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। कहा पन्तनगर एयरपोर्ट का विस्तार कर उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। केन्द्र और राज्य स्तर पर इसकी नियमित समीक्ष की जा रही है।

दूसरी ओर विधायक तिलकराज बेहड़ ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि बस्तियां उजाड़ने से पहले मुझ पर बुल्डोजर चलाना होगा। बेहड़ ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आ रही संजय कालोनी, मस्जिद कालेनी व इन्दिर कालोनी की भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तान्तरित कर दी है। इसके चहले यहाँ बने गरीबों के मकान और झोपड़ियां टूटने हैं, जिसका पुरजोर विरोध होगा। कहा कि सरकार पहले इन लोगों को कहीं बसाने की व्यवस्था करे और उनके निर्माण का पूरा मुआवजा दे। कहा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला यहाँ के लोगों को मलिन बस्तियां की बात कह कर गुमराह कर रहे हैं।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

हिमालय के लिए...

प्रथम पृष्ठ का शेष

उजाड़ने वाले बाँधों, धरती को कम्पयमान करने वाले यांत्रिक विस्फोटों, जैसी घातक प्रवृत्तियों के कारण हिमालयवासियों के सामने जिन्दा रहने का संकट पैदा हो गया है। कौतुहल का विषय है कि एक तरफ स्थानीय हिमालयी वासियों के हक-हकूकों पर कब्जा हुआ तो दूसरी तरफ जल विद्युत परियोजनाओं एव वाइल्ड लाइफ जैसी योजनाओं ने लोगों को विस्थापन के लिये मजबूर कर दिया है। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में दिन-प्रतिदिन पर्यटकों की आमाद बढ़ती ही जा रही है और इसी के साथ-साथ नदियों के सिराहने व ऊँचाई के क्षेत्रों मे कूड़े-कचरे की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई कि अधिकांश जलागम क्षेत्र विषैले व प्रदूषित हो चुके हैं। इसलिये सुझाव दिया जा रहा है कि अर्सिचित ढालदार भूमि, संरक्षित वन, सामूहिक अथवा निजी वन उनका भूमि उपयोग सर्वेक्षण करवाकर पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके तहत फल, चारा, व रेशा प्रजाति के पौधों के रोपण की वृहद योजना बननी चाहिए। ऐसा करने पर मैदानी क्षेत्रों के लिये पहाड़ों से निरन्तर उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, नदियों का बहाव स्थिर होगा और जल की समस्या भी हल होगी। विडम्बना है कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण हिमालय के जलस्रोत, झरने, झीलें, बर्फानी एवं गैर र्फानी नदियाँ सूखती ही जा रही हैं। हिमालय में निवास करने वाले लोग पहले स्वावलम्बी थे जैसे-जैसे उनके प्राकृतिक संसाधनों पर व्यवसायिक परियोजनाएँ संचालित होती गईं वैसे-वैसे वे पलायन करते गए। आलम यह है कि जंगल के प्रहरी के रूप में अब कुछ परम्परानुमा फौजें ही तैनात दिखाई दे रही हैं।कौतुहल का विषय है कि एक तरफ स्थानीय हिमालयी वासियों के हक-हकूकों पर कब्जा हुआ तो दूसरी तरु जल विद्युत परियोजनाओं एव वाइल्ड लाइफ जैसी योजनाओं ने लोगों को विस्थापन के लिये मजबूर कर दिया है। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में दिन-प्रतिदिन पर्यटकों की आमाद बढ़ती ही जा रही है और इसी के साथ-साथ नदियों के सिराहने व ऊँचाई के क्षेत्रों मे कूड़े-कचरे की मात्र इतनी अधिक बढ़ गई कि अधिकांश जलागम क्षेत्र विषैले व प्रदूषित हो चुके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय लोगों के साथ अब तक कोई कारगर परियोजना सामने नहीं है। मगर लोक पर्यटन जैसी प्रक्रिया में कुछ युवकों ने आरम्भ कर रखी है। 2014 में एनडीए अपने घोषणा पत्र के जिन वादों के साथ सत्ता में आया था, उसमें हिमालय के विषय पर एक अलग यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा भी शामिल थी। यद्यपि देश के प्रायः सारे विश्वविद्यालयों में हिमालय के नाम पर कोई न कोई शोध कार्य होते रहते हैं। गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान तो केवल हिमालय के विषय पर ही केन्द्रित होकर काम करता रहा है। यह संस्थान एक ऐसा स्रोत है, जहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के हिमालय की जलवायु, पर्यावरण और यहाँ के निवासियों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है।

उत्तराखण्ड में हिमालय दिवस इसलिए मनाने का निर्णय हुआ था कि केन्द्र और हिमालयी राज्यों की सरकारें अलग से हिमालय की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखकर कोई ऐसा विकास का मॉडल तैयार करेंगी, जिससे हिमालय का विनाश रुक सके। बुग्याल एक तरह के नम क्षेत्र (वेटलैंड) के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ पर जड़ी-बूटियों के अपार भण्डार हैं। पुराने समय मे इन बुग्यालों तक केवल भेड़-बकरी को लेकर गड़रिये पहुँच जाते थे। बाद में गुज्जर समुदाय के लोग भी सैकड़ों भैंसों के साथ वहाँ रहने लगे क्योंकि यहाँ की मखमली घास पशुओं की बहुत सारी बीमारियों को खत्म भी करती है, दूध की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। शीतकाल शुरू होते ही सभी पशुचारक बुग्यालों को छोड़कर तराई में रहने आ जाते हैं। उनका आने-जाने का यह क्रम हर वर्ष बना रहता है। अब बुग्यालों के बीच पर्यटकों की भी बड़ी संख्या में आवाजाही बढ़ गई है। यहाँ तक कि ऐसे स्थानों का इस्तेमाल उत्सवों, शादी-ब्याह रचाने, निजी बेहतर जीवन के रूप में हो रहा है। ताजा उदाहरण है जून, 2019 के तीसरे सप्ताह का जब औली में गुप्ता बन्धुओं की शाही सादी के कारण यहाँ पर्यावरण प्रदूषण की भारी समस्या पैदा हुई। हिमालयी ग्लेशियर, बुग्याल, जंगल के प्रति हमारी इस नासमझी ने ही हिमालय को खतरे में डाल दिया है।

राज्य निर्माण के 20 वर्ष बाद भी उत्तराखण्ड में हालात बदले नहीं हैं। दिल्ली से चलने वाले राष्ट्रीय पार्टियों की सरकारों ने उत्तराखण्ड को दूषित किया है। जलवायु परिवर्तन केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक चिन्ता है, जिसके लिए इन समस्याओं को वैश्विक परिदृश्य से ही समझना होगा। संस्था एनटीपीसी को जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। जोशीमठ दो-तीन हजार फीट तक की ऊँचाई पर कोई परियोजना नहीं बननी चाहिए। उत्तराखण्ड को वर्तमान में चल रहे विकास के मॉडल की जरूरत नहीं हैलोगों की आजीविका के साधनों का संरक्षण हो, जिसके विषय पर पिछले दस वर्षों में केन्द्र सरकार को सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों और आम जनता ने कई सुझाव पत्र भेजे हैं। जिसमें कई लोगों के हस्ताक्षर हैं, इस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। अब स्थिति यह है कि हिमालय दिवस हो या साल के अन्य दिनों में हिमालय के नाम पर होने वाली बैठकें चिन्ता तक सिमट रही हैं। इन बैठकों में मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव स्तर के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। फिर भी आधुनिक विकास में निर्माण कार्यों के जो मानक मैदानों के लिए बनाए गए हैं, उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। नतीजतन ग्लेशियरों के निकट बेहिचक भारी निर्माण कार्य हो रहे है। लाखों दुर्लभ वन प्रजातियां, जैव विविधता, आदि नष्ट हो रही हैं। नदियों के दोनों किनारों पर निर्माण कार्यों का मलबा पड़ा है। बाढ़ और भूस्खलन कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। निर्माण कार्यों के ढांचे इतने कमजोर बने हैं कि उनकी बुनियाद हिल रही है। मीडिया और पर्यावरण कार्यकर्ता इन गम्भीर समस्याओं की ओर लगातार ध्यानाकर्षत कर रहे हैं। अब यह बात हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं। यानी सरकारें समस्या का समाधान ढूंढ भी नहीं पा रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारों व राजनितिक दलों के सांसदो ने समय-समय पर हिमालय के विषय पर विचार करते रहे है। लेकिन वर्तमान में हिमालय विकास का कोई ऐसा विकास मॉडल नहीं बनाया गया है, जिससे बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, हिमालय वासियों का पानी और जवानी हिमालय के काम आ सके और हिमालय को अनियंत्रित छेड़छाड़ से बचाने की प्राथमिकता हो। हिमालय नीति की मांग आजादी के बाद देश की संसद के सामने कई बार उठाई गई है। इस पर कई अध्ययन एवं अनुसंधान हुये हैं। ग्लेश्यिरों, पर्वतों, नदियों, जैविक विविधताओं की दृष्टि से सम्पन्न हिमालयी प्रख्रति और संस्ख्रति का ध्यान योजनाकारों को विशेष रूप से करना चाहिये तथा ग्रीन बोनस यहां की ग्राम सभाओं को मिलना चाहिये। इसको ध्यान में रखकर हिमालय क्षेत्र में रह रहे लोगों, सामाजिक अभियानों तथा आक्रामक विकास नीति को चुनौती देने वाले कार्यकर्ताओं व पर्यावरणविदों ने कई बार समग्र हिमालय नीति बनाने के लिये केन्द्र सरकार को सुझाव दिये हैं। इसके परिणामस्वरुप ही हिमालय की पवित्र नदियाँ, जलवायु परिवर्तन, लगातार आपदाओं के कारण मैदानी क्षेत्रों पर पड़ रहे प्रभाव को ध्यान में रखते हुये हिमालय लोकनीति का दस्तावेज तैयार हुआ है। जिसके द्वारा हिमालय के लिये अलग विकास नीति की माँग की जा रही है प्राथमिकता में किया जा सके पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर बात करनी चाहिए। ये अजीब सी परिस्थिति है कि स्थानीय लोगों को भी कोई चिन्ता है। इस तरह के उम्दा कार्यक्रम हिमालय पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ स्वरोजगार के लिये भी मिशाल है। लेकिन प्रहसन आज भी यह है कि कब और कैसे हिमालय क्षेत्र में विकास की नियोजित परियोजनाएँ बनेंगी। ऐसे अनसुलझे सवालों को लेकर हिमालय दिवस की सार्थकता है। जगजाहिर यह है कि शिमला कनक्लेव में तत्काल पर्यावरण मंत्री ने ग्रीन बोनस की घोषणा करते हुए यह भी आगाह किया था कि अपने देश के वैज्ञानिक पर्यावरण जैसे सम्वेदनशील विषय को लेकर कम-से-कम एक राय प्रस्तुत करें ताकि भविष्य में कोई ठोस निर्णय लिया जा सके।

मास्टर प्लान बनाकर गुंजी में बसाया जाएगा शिवधाम

धारचूला। गुंजी, नाभीढांग, कुटी, नौटी, बूंदी के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार प्रयासरत है। भविष्य में गुंजी को मास्टर प्लान के माध्यम से शिवधाम बनाया जाएगा जिसमें स्थानीय लोगों के भी सुझाव लिए जाएंगे।

यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कही है। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आदि कैलास में श्रद्धालुओं और आईटीबीपी के जवानों के साथ योग करने पहुँचे सीएम ने कहा कि आदि कैलास के प्राकृतिक सौन्दर्य से बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद होनी है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे। ऊनी कालीन उद्योग यहाँ की आर्थिकी का आधार रहा है, इसे बढ़ावा देने का प्रयास होगा। सीएम ने पार्वती सरोवर के निकट शिव मन्दिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कहा कि इस क्षेत्र में नगरीकरण में निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण में स्थानीय वास्तुकला को ध्यान में रखते शतप्रतिशत होमस्टे पर आधारित पर्यटन विकसित किया जायेगा।

मेरा प्रिय गाँव मर्तोली (मर्तोली धाम)

हम जोहार जोहार के, मर्तोली गाँव है हमारा,
हम मर्तोलिया मर्तोली के, माँ नन्दामाई है हमारी।
हम एक कविता सुनाएंगे गाँव का परिचय कराएंगे,
तनिक पास आकर बैठो तो, गाँव का पिटारा खोल देंगे।
हमें तो हमारा मर्तोली गाँच ही अति प्यारा है,
यह गाँच पूरे जोहार भूमि में सबसे न्यारा है।
माँ नन्दामाई की कृपा से सुख और शान्ति यहाँ है,
इस पावन भूमि में भूत-प्रेत का भय नहीं है।
माँ नन्दामाई की कृपा का एहसास हम सबको होता है,
यहाँ की जल, जमीन और जलवायु से हमारा नाता है।
इस देवभूमि वालों का रहन-सहन बोली-भाषा एक है,
इस धरती का खानपान और जलवायु हमेशा एक है।
तालों में ताल नैनीताल, वनों में वन भूर्जवन,
यहीं है नन्दादेवी, नन्दाकोट, देश की है शान।
भूर्जवन में है कस्तूरी मृग और डफिया-मुनाल,
गाँव में है आलू-फाफर-सरसों का खेत-खलिहान।
रंग-विरंगे फूल खिले हैं मर्तोली सेम का,
रंग विरंगी बहार आई है मर्तोली गाँ मा।
गोरी और मर्तोली गंगा का पवित्र संगम यहाँ है,
इसका हमें अभिमान नहीं, हमारा स्वाभिमान है।
हम अपनी मिट्टी को न भूल सकते ना भुला सकते,
हम अपनी मिट्टी से जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे।
जब तक सृष्टि में देवी-देवताओं का अस्तित्व रहेगा,
तब तक माँ नन्दामाई थान, मर्तोली धाम रहेगा।
हम उस गाँव के वासी हैं, जहाँ मर्तोली गंगा बहती है,
हम उस गाँव के निवासी हैं, जिसके रक्षक नन्दामाई है।
हे नन्दामाई! आपकी माया अपरम्पार है,
आप करती रक्षा हम सक बी बारम्बार हैं।
मर्तोली एक हाम है जहाँ नन्दामाई का थान है,
यह धरती नहीं हमारे लिए स्वर्ग समान है।
मर्तोली का नन्दाष्टमी पर्व होता है देखने लायक,
स्थानीय ढुस्का-चांचरी होता है देखने-सुनने लायक।
जो स्वाद वहाँ के आलू-फाफर की पूली-चुन्नी में होता है,
ऐसा स्वाद दुनिया में कहीं और जगह मिलता नहीं है।
जो स्वाद नमकीन ज्या के साथ सक्तू का होता है,
वह दूध की मीठी चाय व काफी में कहाँ होता है?
हिमाच्छादित पर्वत देखना है तो जोहार चले आओ,
भूर्जवन सुन्दर गाँव देखना हो तो मर्तोली चले जाओ।
मेरे मर्तोली गाँव की मिट्टी से अनोखी खुशबू आती है,
दूर प्रदेश में रहकर भी मर्तोली की याद हमेशा आती है।
जय माँ नन्दामाई! जय मर्तोली धाम! जय नन्दामाई!

-ललित सिंह मर्तोलिया

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

घर से बाहर अपनों का साथ

होटल लक्ष्य इन

मदकोट

सम्पर्क 7351285555

नरेन्द्र सिंह रावत

न तेरा न मेरा Thats

APNA GHAR चौकोड़ी

HOTEL RESTRO BANQUET

मो.- 9458920379, 6396098804

YOGA MEDITATION | LIVE MUSIC | HOMELY FOOD | BIRTHDAY WEDDING

Near by- (माँ कोटगाड़ी, नौलिंग देव, पातालभुवनेश्वर)

पितृछाया- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. जोगासिंह मर्तोलिया

पिघलता हिमालय स्थापना के 47 वर्ष में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ-

---

Hotel Bala Paradise

Tiksain, Munsiari

Ph. 05961222237, 9412951678

Hayat Paradise

Bus Station Munsiari

Ph. 09411556700, 9997733070

धमोत होम स्टे

धरमघर/चकोड़ी

(एडवेंचर जोन, ट्रेकिंग, माउंटेन वाइकिंग, स्थानीय व्यंजन)

www.mountainheights.in

मो. 9760007148

खड़क सिंह बगड्वाल

अध्यक्ष

(पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच)

जगदम्बा नगर

हल्द्वानी

माँ नन्दा आयरन एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल

भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी

(सीमेन्ट, सरिया, टाइल, पेण्ट, सेनेटरी, हार्डवेयर)

गोदाम- जोहार एसोसिएट्स, बच्चीनगर- १, कमलुवागांजा, हल्द्वानी

मो.- 7409440813, 7500619761

होटल माँ नन्दादेवी एण्ड बारातघर

नानासेम, मुनस्यारी

गणेश सिंह मर्तोलिया एण्ड सन्स

हार्डवेयर, बिल्डिंग मैटीरियल, जनरल आर्डर सप्लायर्स

फोन सम्पर्क- 05961-222236 8958525979, 9411134775

खजान चन्द (गुड्डू)

पूर्व उपाध्यक्ष(राज्यमंत्री)

उत्तराखण्ड सरकार विधानसभा

गंगोलीहाट

खजान कॉम्पलेक्स, दमुवाढूंगा

हल्द्वानी

MARTOLIA FURNITURE

A unit of Martolia Enterprises

Pilikothi, Haldwani

Mob- 8057167777, 7906752084, 8650427229

Enjoy Beauty of Himalaya at

MARTOLIA LODGE

Family Guest House- Sarmoly, Munsiyari

A Home Away From Home & Home Stay

Phone: (05961) 222287

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीमती गीता उप्रेती द्वारा पिघलता हिमालय, जे०के०पुरम, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड से प्रकाशित एवं शक्ति प्रेस, जे०के०पुरम, सेक्टर डी, छोटी मुखानी, हल्द्वानी(नैनीताल) से मुद्रित।

सम्पादक: श्रीमती गीता उप्रेती फोन/मोबाइल 9458961490, 9411770280, 9411301014,

editorpighaltahimalay@gmail.com

Website- www.pighaltahimalay.com

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)